International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 05-10-2025, Accepted: 05-11-2025, Published: 20-11-2025
Volume 11, Issue 6, 2025, Page No. 194-200

राजनीति और युवाओं की अपेक्षाएँरू लोकतांत्रिक शासन में चुनौतियाँ एवं अवसर

डॉ0 सतीश चन्द
सहायक आचार्य, बाबा फरीद कॉलेज ऑफ़ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, फरीदपुर, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश
इक्कीसवीं सदी में वैश्वीकरण, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल मीडिया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तीव्र आर्थिक परिवर्तन तथा बढ़ती सामाजिक जागरूकता ने युवाओं की राजनीतिक अपेक्षाओं को व्यापक रूप से परिवर्तित किया है। आज का युवा केवल मतदान तक सीमित नागरिक नहीं है, बल्कि वह पारदर्शी, उत्तरदायी, सहभागी तथा परिणामोन्मुख लोकतांत्रिक शासन की अपेक्षा करता है। प्रस्तुत शोध–लेख का उद्देश्य लोकतांत्रिक शासन के संदर्भ में युवाओं की बदलती अपेक्षाओं तथा राजनीतिक नेतृत्व के समक्ष उपस्थित चुनौतियों एवं अवसरों का विश्लेषण करना है। लेख में यह विवेचना की गई है कि शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, डिजिटल शासन, पर्यावरणीय उत्तरदायित्व, सामाजिक न्याय, सुशासन तथा नैतिक राजनीति जैसे मुद्दे किस प्रकार युवाओं की प्राथमिकताओं के केंद्र में आ गए हैं। साथ ही भारत एवं वैश्विक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में युवाओं की राजनीतिक भागीदारी, डिजिटल नागरिकता तथा सार्वजनिक नीतियों के प्रभाव का आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। अध्ययन का निष्कर्ष है कि लोकतांत्रिक शासन की सफलता केवल संस्थागत संरचनाओं पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि राजनीतिक नेतृत्व युवाओं की बदलती आकांक्षाओं को किस सीमा तक समझता और उन्हें नीति–निर्माण में सम्मिलित करता है। समावेशी शासन, पारदर्शिता, नवाचार, डिजिटल सहभागिता तथा युवाओं की निर्णय–निर्माण प्रक्रिया में सार्थक भागीदारी भविष्य के लोकतंत्र को अधिक उत्तरदायी, न्यायपूर्ण और सतत बना सकती है।

मुलशब्दः लोकतंत्र, युवा अपेक्षाएँ, राजनीतिक नेतृत्व, सुशासन, सार्वजनिक नीति

लोकतंत्र केवल शासन प्रणाली नहीं, बल्कि नागरिकों की आकांक्षाओं, अधिकारों और सहभागिता पर आधारित एक सतत सामाजिक–राजनीतिक प्रक्रिया है। किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने नागरिकों, विशेषकर युवाओं की अपेक्षाओं को किस सीमा तक समझता और उन्हें नीति–निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित करता है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में युवा केवल भविष्य के नागरिक नहीं, बल्कि वर्तमान के सक्रिय परिवर्तनकारी (Change Agents) के रूप में उभरकर सामने आए हैं। यही कारण है कि आज लोकतांत्रिक शासन की गुणवत्ता का मूल्यांकन केवल आर्थिक विकास से नहीं, बल्कि युवाओं के विश्वास, सहभागिता, अवसरों और संतुष्टि के आधार पर भी किया जाने लगा है।

भारत विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है। जनसांख्यिकीय दृष्टि से यह स्थिति भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करती है। यदि युवाओं की ऊर्जा, नवाचार क्षमता और नेतृत्व कौशल का प्रभावी उपयोग किया जाए तो यह जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend) राष्ट्रीय विकास का सबसे बड़ा आधार बन सकता है। इसके विपरीत यदि युवाओं की अपेक्षाओं की उपेक्षा होती है तो यही लाभांश सामाजिक असंतोष, राजनीतिक अविश्वास तथा आर्थिक चुनौतियों का कारण भी बन सकता है।

इक्कीसवीं सदी के प्रारम्भ से ही वैश्वीकरण, इंटरनेट, सोशल मीडिया, डिजिटल अर्थव्यवस्था तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने युवाओं के दृष्टिकोण में उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। पहले जहाँ राजनीतिक अपेक्षाएँ मुख्यतः मूलभूत सुविधाओं, रोजगार तथा सुरक्षा तक सीमित थीं, वहीं आज का युवा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पारदर्शी शासन, डिजिटल सेवाएँ, पर्यावरण संरक्षण, लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय, नवाचार, उद्यमिता तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धा जैसे व्यापक विषयों को अपनी प्राथमिकता में सम्मिलित करता है।

आज का युवा राजनीतिक दलों से केवल चुनावी घोषणाएँ नहीं, बल्कि समयबद्ध कार्यान्वयन, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता और परिणाम की अपेक्षा करता है। वह सार्वजनिक नीतियों के निर्माण में अपनी भागीदारी चाहता है तथा डिजिटल माध्यमों के द्वारा शासन से प्रत्यक्ष संवाद स्थापित करने की आकांक्षा रखता है। यही कारण है कि लोकतांत्रिक शासन की पारंपरिक अवधारणाएँ अब सहभागी लोकतंत्र (Participatory Democracy), डिजिटल लोकतंत्र (Digital Democracy) तथा उत्तरदायी शासन (Responsive Governance) की ओर अग्रसर हो रही हैं।

इसके अतिरिक्त, कोविड–19 महामारी के पश्चात युवाओं की प्राथमिकताओं में स्वास्थ्य सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, डिजिटल शिक्षा, रोजगार की स्थिरता तथा सामाजिक सुरक्षा जैसे नए आयाम भी जुड़ गए हैं। जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा तथा वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं ने भी उनकी राजनीतिक अपेक्षाओं को नया स्वरूप प्रदान किया है।

इन परिस्थितियों में राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। लोकतांत्रिक नेतृत्व केवल शासन संचालन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह नागरिकों के विश्वास का निर्माण, संस्थागत उत्तरदायित्व की स्थापना तथा भविष्य की विकास दिशा का निर्धारण भी करता है। यदि राजनीतिक नेतृत्व युवाओं की आकांक्षाओं को समझकर समावेशी एवं दूरदर्शी नीतियाँ अपनाता है, तो लोकतंत्र अधिक सुदृढ़, उत्तरदायी और स्थायी बन सकता है।

इसी संदर्भ में प्रस्तुत शोध–लेख का उद्देश्य इक्कीसवीं सदी में युवाओं की बदलती राजनीतिक अपेक्षाओं का विश्लेषण करना, लोकतांत्रिक शासन के समक्ष उपस्थित चुनौतियों एवं अवसरों का मूल्यांकन करना तथा ऐसी नीतिगत दिशाएँ प्रस्तुत करना है जो युवा–केंद्रित, समावेशी और उत्तरदायी लोकतांत्रिक व्यवस्था के निर्माण में सहायक सिद्ध हों।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत लेख के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं

1. इक्कीसवीं सदी में युवाओं की राजनीतिक अपेक्षाओं में आए परिवर्तन का विश्लेषण करना।

2. लोकतांत्रिक शासन में युवाओं की भूमिका एवं सहभागिता का अध्ययन करना।
3. राजनीतिक नेतृत्व के प्रति युवाओं की बदलती अपेक्षाओं का मूल्यांकन करना।
4. लोकतांत्रिक शासन के समक्ष उपस्थित प्रमुख चुनौतियों एवं अवसरों का विश्लेषण करना।
5. युवा–केंद्रित सार्वजनिक नीतियों हेतु व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करना।

अध्ययन की आवश्यकता एवं प्रासंगिकता

वर्तमान समय में विश्व की लगभग प्रत्येक लोकतांत्रिक व्यवस्था युवा मतदाताओं, डिजिटल नागरिकता तथा सामाजिक परिवर्तन की नई चुनौतियों का सामना कर रही है। राजनीतिक दलों की कार्यशैली, चुनावी अभियान, सार्वजनिक विमर्श तथा नीति–निर्माण की प्रक्रियाएँ तीव्र गति से बदल रही हैं। इन परिवर्तनों के केंद्र में युवा वर्ग स्थित है।

भारतीय लोकतंत्र में भी युवाओं का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। चुनावों में प्रथम बार मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या प्रत्येक वर्ष बढ़ रही है। साथ ही, सोशल मीडिया, ऑनलाइन अभियानों तथा डिजिटल संवाद के माध्यम से युवा प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक विमर्श को प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि वर्तमान युवा राजनीति से क्या अपेक्षा रखता है और लोकतांत्रिक संस्थाएँ उन अपेक्षाओं को किस सीमा तक पूरा कर पा रही हैं।

इस अध्ययन की प्रासंगिकता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि लोकतंत्र की स्थिरता केवल चुनावों पर नहीं, बल्कि नागरिकों के विश्वास, सहभागिता तथा शासन की उत्तरदायित्वशीलता पर आधारित होती है। यदि युवा लोकतांत्रिक संस्थाओं पर विश्वास बनाए रखते हैं तो लोकतंत्र अधिक सुदृढ़ होता है; अन्यथा राजनीतिक उदासीनता, ध्रुवीकरण तथा असंतोष जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

राजनीति और युवा अपेक्षाएँ: वैचारिक परिप्रेक्ष्य

राजनीति का मूल उद्देश्य सार्वजनिक हित की रक्षा, संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण तथा समाज के विभिन्न वर्गों की आकांक्षाओं का संतुलित समायोजन करना है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीति नागरिकों और राज्य के मध्य संवाद का प्रमुख माध्यम होती है। दूसरी ओर, युवा अपेक्षाएँ उन सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं जिन्हें युवा वर्ग राज्य और शासन से पूरा होते हुए देखना चाहता है।

बीसवीं शताब्दी की राजनीति मुख्यतः विचारधारात्मक संघर्ष, दलगत निष्ठा और पारंपरिक नेतृत्व पर आधारित थी। किंतु इक्कीसवीं सदी में राजनीति का स्वरूप अधिक नागरिक–केंद्रित, डिजिटल और परिणामोन्मुख हो गया है। आज का युवा किसी राजनीतिक दल के प्रति स्थायी निष्ठा के बजाय उसके प्रदर्शन, पारदर्शिता, जवाबदेही और सार्वजनिक नीतियों का मूल्यांकन करता है। इस परिवर्तन ने लोकतांत्रिक राजनीति को अधिक प्रतिस्पर्धी, संवादात्मक और उत्तरदायी बनाया है।

युवा अपेक्षाओं को पाँच प्रमुख आयामों में समझा जा सकता है

- **आर्थिक अपेक्षाएँ:** गुणवत्तापूर्ण रोजगार, उद्यमिता, स्टार्टअप समर्थन और आर्थिक सुरक्षा।
- **शैक्षिक अपेक्षाएँ:** वैश्विक स्तर की शिक्षा, कौशल विकास, अनुसंधान और नवाचार।
- **सामाजिक अपेक्षाएँ:** समान अवसर, सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता और समावेशन।
- **राजनीतिक अपेक्षाएँ:** पारदर्शिता, जवाबदेही, भ्रष्टाचार–मुक्त शासन और नीति–निर्माण में भागीदारी।
- **डिजिटल अपेक्षाएँ:** ऑनलाइन सेवाएँ, डिजिटल अधिकार, सूचना की उपलब्धता और त्वरित प्रशासनिक प्रतिक्रिया।

इन्हीं अपेक्षाओं के आधार पर आज का युवा लोकतांत्रिक शासन की गुणवत्ता का मूल्यांकन करता है। इसलिए समकालीन राजनीति में युवा केवल मतदाता नहीं, बल्कि नीति–निर्माण का एक सक्रिय हितधारक (Stakeholder) बन चुका है।

इक्कीसवीं सदी में युवाओं की बदलती अपेक्षाएँ

इक्कीसवीं सदी को सूचना, प्रौद्योगिकी, वैश्वीकरण, ज्ञान–आधारित अर्थव्यवस्था तथा तीव्र सामाजिक परिवर्तन का युग कहा जाता है। इस युग में युवाओं की सोच, जीवन शैली, कार्य संस्कृति, नागरिक चेतना और राजनीतिक दृष्टिकोण में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। जहाँ बीसवीं शताब्दी का युवा मुख्यतः रोजगार, शिक्षा और बुनियादी नागरिक सुविधाओं तक सीमित अपेक्षाएँ रखता था, वहीं आज का युवा शासन से अधिक उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, नवाचार और सहभागी लोकतंत्र की अपेक्षा करता है। यह परिवर्तन केवल तकनीकी विकास का परिणाम नहीं है, बल्कि सामाजिक जागरूकता, वैश्विक संपर्क और लोकतांत्रिक मूल्यों के विस्तार का भी परिणाम है।

आज का युवा स्वयं को केवल मतदाता नहीं मानता, बल्कि नीति–निर्माण, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्रीय विकास का सक्रिय भागीदार समझता है। वह राजनीतिक दलों की विचारधारा से अधिक उनके कार्य–निष्पादन, सुशासन, भ्रष्टाचार–नियंत्रण, डिजिटल सेवाओं, रोजगार सृजन तथा पर्यावरणीय उत्तरदायित्व को महत्व देता है। यही कारण है कि लोकतांत्रिक शासन के लिए युवाओं की अपेक्षाओं को समझना पहले की तुलना में कहीं अधिक आवश्यक हो गया है।

1. रोजगार और आर्थिक सुरक्षा की अपेक्षा

वर्तमान समय में युवाओं की सबसे बड़ी अपेक्षा सम्मानजनक, स्थायी और गुणवत्तापूर्ण रोजगार की है। वैश्वीकरण और स्वचालन (Automation) ने रोजगार के स्वरूप को बदल दिया है। पारंपरिक नौकरियों के साथ–साथ स्टार्टअप, डिजिटल उद्यमिता, फ्रीलांसिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विज्ञान और हरित अर्थव्यवस्था जैसे नए क्षेत्रों का विस्तार हुआ है।

युवा चाहते हैं कि सरकार

- रोजगार सृजन को प्राथमिकता दे।
- कौशल विकास कार्यक्रमों को उद्योगों की आवश्यकताओं से जोड़े।
- स्टार्टअप एवं नवाचार को प्रोत्साहित करे।
- स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए।
- भविष्य की अर्थव्यवस्था के अनुरूप नई रोजगार नीतियाँ बनाए।

यदि रोजगार संबंधी अपेक्षाएँ पूरी नहीं होतीं, तो युवाओं में निराशा, प्रवासन तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति असंतोष बढ़ सकता है।

2. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास

आज का युवा केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं चाहता, बल्कि ऐसी शिक्षा चाहता है जो उसे वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करे। वह व्यावहारिक ज्ञान, डिजिटल दक्षता, अनुसंधान क्षमता, नवाचार, उद्यमिता और बहुविषयक शिक्षा को प्राथमिकता देता है।

नई पीढ़ी की अपेक्षाएँ निम्नलिखित हैं

- विश्वस्तरीय उच्च शिक्षा।

- उद्योग–उन्मुख पाठ्यक्रम।
- डिजिटल शिक्षण संसाधन।
- अनुसंधान एवं नवाचार के अवसर।
- जीवन–कौशल (Life Skills) एवं नेतृत्व विकास।

इस प्रकार शिक्षा अब केवल ज्ञान प्राप्ति का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक गतिशीलता और आर्थिक अवसरों का आधार बन गई है।

3. पारदर्शी एवं उत्तरदायी शासन

डिजिटल युग के युवा शासन से अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की अपेक्षा करते हैं। वे सरकारी योजनाओं के प्रभाव, सार्वजनिक व्यय, नीति–निर्माण तथा प्रशासनिक निर्णयों के संबंध में खुली जानकारी चाहते हैं।

युवाओं की प्रमुख अपेक्षाएँ हैं

- भ्रष्टाचार–मुक्त प्रशासन।
- समयबद्ध सेवाएँ।
- डिजिटल शिकायत निवारण।
- सार्वजनिक सूचना तक सरल पहुँच।
- उत्तरदायी राजनीतिक नेतृत्व।

आज का युवा चुनावी वादों के बजाय वास्तविक उपलब्धियों के आधार पर राजनीतिक नेतृत्व का मूल्यांकन करता है।

4. सामाजिक न्याय एवं समान अवसर

समकालीन युवा जाति, धर्म, लिंग, भाषा तथा क्षेत्रीय पहचान से परे समान अवसरों और सामाजिक न्याय की अपेक्षा रखते हैं। वे ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहते हैं जहाँ प्रत्येक नागरिक को उसकी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर मिले।

विशेष रूप से युवा निम्नलिखित मुद्दों को महत्व देते हैं

- लैंगिक समानता।
- सामाजिक समावेशन।
- दिव्यांगजनों के अधिकार।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का उत्थान।
- भेदभाव–मुक्त समाज।

इस परिवर्तन ने लोकतांत्रिक विमर्श को अधिक समावेशी बनाया है।

5. पर्यावरणीय उत्तरदायित्व

इक्कीसवीं सदी का युवा जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण तथा सतत विकास को राजनीति का अभिन्न भाग मानता है। वह चाहता है कि राजनीतिक दल चुनावी घोषणापत्रों में पर्यावरणीय नीतियों को पर्याप्त महत्व दें।

इस दृष्टि से युवाओं की अपेक्षाएँ निम्नलिखित हैं

- स्वच्छ ऊर्जा।
- हरित रोजगार।
- जल संरक्षण।
- टिकाऊ शहरी विकास।
- जलवायु परिवर्तन पर प्रभावी नीति।

यह परिवर्तन दर्शाता है कि युवा अब केवल वर्तमान नहीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के हितों को भी महत्व देते हैं।

राजनीतिक नेतृत्व के प्रति युवाओं की बदलती अपेक्षाएँ

इक्कीसवीं सदी में राजनीतिक नेतृत्व की पारंपरिक अवधारणा में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। पहले नेतृत्व मुख्यतः करिश्माई व्यक्तित्व, दलगत निष्ठा तथा चुनावी सफलता से जुड़ा माना जाता था, जबकि आज नेतृत्व का मूल्यांकन उसके नैतिक आचरण, पारदर्शिता, निर्णय क्षमता, तकनीकी समझ और जनसंपर्क के आधार पर किया जाता है।

आज का युवा ऐसे नेतृत्व की अपेक्षा करता है जो

- ईमानदार और पारदर्शी हो।
- वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाए।
- डिजिटल माध्यमों से संवाद करे।
- युवाओं की समस्याओं को समझे।
- दीर्घकालिक विकास योजनाएँ बनाए।
- सामाजिक विविधता का सम्मान करे।

राजनीतिक नेतृत्व की विश्वसनीयता अब केवल भाषणों से नहीं, बल्कि नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन और सार्वजनिक उत्तरदायित्व से निर्धारित होती है।

डिजिटल लोकतंत्र और युवाओं की राजनीतिक भागीदारी

डिजिटल क्रांति ने लोकतंत्र की प्रकृति को गहराई से प्रभावित किया है। सोशल मीडिया, ऑनलाइन अभियान, ई–गवर्नेंस, डिजिटल परामर्श और ऑनलाइन जनसुनवाई जैसे माध्यमों ने नागरिकों और सरकार के बीच संवाद को अधिक त्वरित और व्यापक बनाया है।

युवा इन मंचों का उपयोग

- राजनीतिक जानकारी प्राप्त करने,
- सार्वजनिक मुद्दों पर विचार व्यक्त करने,
- जन–अभियानों में भाग लेने,
- नीति–निर्माण पर प्रतिक्रिया देने,
- सामाजिक आंदोलनों को संगठित करने के लिए करते हैं।

डिजिटल लोकतंत्र ने नागरिक सहभागिता को बढ़ाया है, किंतु इसके साथ कई चुनौतियाँ भी उत्पन्न हुई हैं, जैसे—

- दुष्प्रचार (Misinformation)
- फेक न्यूज़
- साइबर ट्रोलिंग
- ऑनलाइन घृणा भाषण
- एल्गोरिदि्मक पक्षपात
- डिजिटल विभाजन

इसलिए डिजिटल लोकतंत्र को प्रभावी बनाने के लिए डिजिटल साक्षरता, मीडिया साक्षरता तथा उत्तरदायी डिजिटल नागरिकता का विकास आवश्यक है।

लोकतांत्रिक शासन और युवा सहभागिता

लोकतांत्रिक शासन का मूल आधार नागरिक सहभागिता है। यदि युवा केवल मतदान तक सीमित रहें, तो लोकतंत्र की संभावनाएँ सीमित हो जाती हैं। इसके विपरीत यदि वे नीति–निर्माण, स्थानीय शासन, सामाजिक आंदोलनों, सार्वजनिक विमर्श तथा सामुदायिक विकास में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, तो लोकतंत्र अधिक सुदृढ़ बनता है।

युवा सहभागिता निम्न स्तरों पर विकसित की जा सकती है

- स्थानीय निकायों में भागीदारी।

- युवा संसद।
- छात्र परिषदें।
- नीति परामर्श मंच।
- स्वयंसेवी संगठन।
- सामाजिक नवाचार कार्यक्रम।
- डिजिटल नागरिक मंच।

इन माध्यमों से युवाओं में नेतृत्व क्षमता, लोकतांत्रिक मूल्य तथा उत्तरदायित्व की भावना विकसित होती है।

युवा और लोकतांत्रिक विश्वास

लोकतंत्र की सफलता केवल संस्थागत संरचनाओं पर निर्भर नहीं करती, बल्कि नागरिकों के विश्वास पर भी आधारित होती है। यदि युवा न्यायपालिका, निर्वाचन प्रणाली, संसद, मीडिया और प्रशासन पर विश्वास बनाए रखते हैं, तो लोकतंत्र अधिक स्थिर और प्रभावी बनता है।

विश्वास को मजबूत करने वाले प्रमुख तत्व हैं

- निष्पक्ष चुनाव।
- विधि का शासन।
- पारदर्शी प्रशासन।
- भ्रष्टाचार पर नियंत्रण।
- उत्तरदायी सार्वजनिक संस्थाएँ।
- नागरिक अधिकारों का संरक्षण।

जब शासन इन अपेक्षाओं को पूरा करता है, तब युवाओं की लोकतांत्रिक भागीदारी और नागरिक उत्तरदायित्व दोनों में वृद्धि होती है।

लोकतांत्रिक शासन के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ

इक्कीसवीं सदी में लोकतांत्रिक शासन के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती युवाओं की तीव्र गति से बदलती अपेक्षाओं के अनुरूप स्वयं को परिवर्तित करना है। आज का युवा अधिक शिक्षित, तकनीकी रूप से दक्ष, वैश्विक दृष्टिकोण रखने वाला तथा अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति पहले की अपेक्षा अधिक जागरूक है। वह सरकार से केवल प्रशासनिक सेवाओं की अपेक्षा नहीं करता, बल्कि पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, नवाचार और सहभागी शासन की भी मांग करता है। यदि लोकतांत्रिक संस्थाएँ इन अपेक्षाओं को समय पर पूरा नहीं कर पातीं, तो नागरिकों का विश्वास कम होने लगता है और शासन की वैधता प्रभावित होती है।

1. बेरोजगारी और रोजगार की गुणवत्ता

भारत सहित अनेक लोकतांत्रिक देशों में युवाओं के समक्ष रोजगार सबसे बड़ी चुनौती है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद बड़ी संख्या में युवा अपनी योग्यता के अनुरूप रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते। इसके अतिरिक्त स्वचालन (Automation), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence), गिग अर्थव्यवस्था (Gig Economy) तथा बदलते औद्योगिक ढाँचे ने पारंपरिक रोजगार संरचनाओं को भी प्रभावित किया है।

युवाओं की अपेक्षाएँ अब केवल रोजगार प्राप्त करने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे—

- सम्मानजनक वेतन,
- सुरक्षित कार्य वातावरण,
- कैरियर उन्नति,
- सामाजिक सुरक्षा,
- कार्य–जीवन संतुलन,
- नवाचार एवं उद्यमिता के अवसर की भी अपेक्षा रखते हैं।

यदि सार्वजनिक नीतियाँ इन आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित नहीं होतीं, तो युवाओं में आर्थिक असुरक्षा और राजनीतिक असंतोष दोनों बढ़ सकते हैं।

2. लोकतांत्रिक संस्थाओं पर घटता विश्वास

लोकतंत्र की सफलता नागरिकों के विश्वास पर आधारित होती है। जब युवा यह अनुभव करते हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान समय पर नहीं हो रहा या नीति–निर्माण में उनकी आवाज़ को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा, तब लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति उनका विश्वास कम होने लगता है।

विश्वास में कमी के प्रमुख कारण हैं

- भ्रष्टाचार की धारणा।
- निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव।
- नीतियों के क्रियान्वयन में विलंब।
- राजनीतिक ध्रुवीकरण।
- चुनावी वादों और वास्तविक उपलब्धियों के बीच अंतर।
- प्रशासनिक जवाबदेही की कमी।

इस स्थिति में लोकतंत्र की गुणवत्ता केवल संवैधानिक प्रावधानों से नहीं, बल्कि शासन की कार्यकुशलता से निर्धारित होती है।

3. सूचना का अतिरेक और दुष्प्रचार

डिजिटल मीडिया ने राजनीतिक जानकारी को अधिक सुलभ बनाया है, किंतु इसके साथ सूचना की विश्वसनीयता एक गंभीर चुनौती बनकर उभरी है। फेक न्यूज़, भ्रामक प्रचार, डीपफेक तकनीक तथा सोशल मीडिया एल्गोरिद्म अनेक बार युवाओं की राजनीतिक समझ को प्रभावित करते हैं।

इसके परिणामस्वरूप

- लोकतांत्रिक विमर्श का स्तर प्रभावित होता है।
- सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ सकता है।
- संस्थाओं के प्रति अविश्वास उत्पन्न होता है।
- तथ्य और मत के बीच अंतर करना कठिन हो जाता है।

इसलिए डिजिटल नागरिकता तथा मीडिया साक्षरता लोकतांत्रिक शासन की नई आवश्यकता बन गई है।

4. सामाजिक असमानता और समावेशन की चुनौती

यद्यपि लोकतंत्र समान अवसर प्रदान करने का प्रयास करता है, फिर भी सामाजिक एवं आर्थिक असमानताएँ अनेक देशों में बनी हुई हैं। ग्रामीण–शहरी अंतर, लैंगिक असमानता, डिजिटल विभाजन, क्षेत्रीय विषमताएँ तथा आर्थिक विषमता युवाओं के अवसरों को प्रभावित करती हैं।

यदि विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक समान रूप से नहीं पहुँचता, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में असंतोष बढ़ सकता है। इसलिए समावेशी विकास लोकतांत्रिक शासन की मूल आवश्यकता है।

5. मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक दबाव

वर्तमान समय में प्रतियोगिता, बेरोजगारी, आर्थिक असुरक्षा, डिजिटल तुलना (Social Comparison), सामाजिक अपेक्षाएँ तथा भविष्य की अनिश्चितता युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही हैं। लोकतांत्रिक शासन के लिए यह एक नई

नीति–चुनौती है क्योंकि मानसिक रूप से सशक्त युवा ही लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सक्रिय और सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं।

लोकतांत्रिक शासन में उभरते अवसर

यद्यपि चुनौतियाँ गंभीर हैं, फिर भी इक्कीसवीं सदी लोकतंत्र के लिए अनेक नए अवसर भी प्रस्तुत करती है। यदि राजनीतिक नेतृत्व दूरदर्शी हो और सार्वजनिक नीतियाँ युवा–केंद्रित हों, तो वर्तमान परिवर्तन लोकतांत्रिक शासन को अधिक प्रभावी बना सकते हैं।

1. जनसांख्यिकीय लाभांश

भारत विश्व की सबसे युवा आबादी वाले देशों में से एक है। यदि युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य और रोजगार उपलब्ध कराया जाए, तो यह जनसांख्यिकीय संरचना आर्थिक विकास, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का आधार बन सकती है।

युवाओं की ऊर्जा

- उत्पादकता बढ़ा सकती है।
- नवाचार को गति दे सकती है।
- लोकतांत्रिक नेतृत्व को नया स्वरूप दे सकती है।
- सामाजिक परिवर्तन को गति प्रदान कर सकती है।

2. डिजिटल शासन

ई–गवर्नेंस ने नागरिकों और सरकार के बीच संवाद को अधिक सरल, पारदर्शी और त्वरित बनाया है।

डिजिटल शासन के प्रमुख लाभ

- सेवाओं की समयबद्ध उपलब्धता।
- ऑनलाइन शिकायत निवारण।
- पारदर्शी प्रशासन।
- नागरिक सहभागिता।
- नीति–निर्माण में जनमत संग्रह एवं डिजिटल परामर्श।
- डेटा–आधारित निर्णय।

युवा इस प्रकार की शासन प्रणाली को अधिक स्वीकार करते हैं क्योंकि यह उनकी जीवनशैली और अपेक्षाओं के अनुरूप है।

3. नवाचार और उद्यमिता

आज का युवा नौकरी खोजने के साथ–साथ रोजगार सृजनकर्ता (Job Creator) भी बनना चाहता है। स्टार्टअप संस्कृति, सामाजिक उद्यमिता तथा डिजिटल व्यवसाय लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था को नई दिशा प्रदान कर रहे हैं।

यदि सरकार

- उद्यमिता को प्रोत्साहित करे,
- अनुसंधान में निवेश बढ़ाए,
- नवाचार को समर्थन दे,
- युवाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए,

तो लोकतांत्रिक विकास अधिक समावेशी और टिकाऊ बन सकता है।

4. सहभागी लोकतंत्र

समकालीन लोकतंत्र में नागरिक केवल चुनावों के समय सक्रिय नहीं रहते, बल्कि नीति–निर्माण की पूरी प्रक्रिया में भागीदारी चाहते हैं।

युवा निम्नलिखित माध्यमों से लोकतंत्र को अधिक सहभागी बना सकते हैं—

- जन परामर्श।
- स्थानीय शासन।
- युवा संसद।
- डिजिटल मंच।
- नागरिक अभियान।
- नीति संवाद।

इस प्रकार लोकतंत्र प्रतिनिधिक (Representative) से आगे बढ़कर सहभागी (Participatory) स्वरूप ग्रहण कर रहा है।

भारत एवं वैश्विक परिप्रेक्ष्य

विश्व के अनेक लोकतांत्रिक देशों में युवाओं की अपेक्षाओं में उल्लेखनीय समानताएँ दिखाई देती हैं। चाहे विकसित राष्ट्र हों या विकासशील, युवा वर्ग अब बेहतर शिक्षा, सम्मानजनक रोजगार, पारदर्शी शासन, पर्यावरणीय उत्तरदायित्व तथा सामाजिक न्याय को प्राथमिकता देता है। अंतर केवल इतना है कि विभिन्न देशों की राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के कारण इन अपेक्षाओं को पूरा करने के तरीके अलग–अलग हो सकते हैं।

भारत में युवा लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार हैं। बड़ी युवा आबादी चुनावों, सामाजिक आंदोलनों, डिजिटल अभियानों तथा सार्वजनिक विमर्श को प्रभावित करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, डिजिटल शासन, कौशल विकास तथा स्टार्टअप प्रोत्साहन जैसी पहलें युवाओं की बदलती अपेक्षाओं के अनुरूप शासन को पुनर्संगठित करने का प्रयास करती हैं। फिर भी रोजगार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्षेत्रीय असमानता तथा संस्थागत उत्तरदायित्व जैसे क्षेत्रों में निरंतर सुधार की आवश्यकता बनी हुई है।

वैश्विक स्तर पर यह देखा गया है कि जिन लोकतांत्रिक देशों ने शिक्षा, नवाचार, पारदर्शिता, डिजिटल सेवाओं तथा नागरिक सहभागिता को प्राथमिकता दी है, वहाँ युवाओं का लोकतांत्रिक संस्थाओं पर विश्वास अपेक्षाकृत अधिक मजबूत बना हुआ है।

सारणी 1: बीसवीं और इक्कीसवीं सदी के युवाओं की राजनीतिक अपेक्षाओं का तुलनात्मक विश्लेषण

आयाम	बीसवीं शताब्दी	इक्कीसवीं सदी
राजनीति की प्राथमिकता	विचारधारा एवं दल	प्रदर्शन एवं परिणाम
सहभागिता	मतदान तक सीमित	निरंतर नागरिक सहभागिता
सूचना का स्रोत	समाचार पत्र एवं टेलीविजन	सोशल मीडिया एवं डिजिटल मंच
रोजगार अपेक्षा	सरकारी नौकरी	विविध कैरियर एवं उद्यमिता
शासन से अपेक्षा	प्रशासनिक सेवाएँ	पारदर्शिता, जवाबदेही एवं डिजिटल सेवाएँ
नेतृत्व का मूल्यांकन	व्यक्तित्व आधारित	कार्य–निष्पादन आधारित
नागरिक भूमिका	मतदाता	नीति–निर्माण का सहभागी
वैश्विक दृष्टिकोण	सीमित	वैश्विक एवं डिजिटल नागरिकता

विश्लेषणात्मक विमर्श

उपरोक्त विश्लेषण स्पष्ट करता है कि युवाओं की अपेक्षाओं में आया परिवर्तन केवल पीढ़ीगत परिवर्तन नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की प्रकृति में हो रहे संरचनात्मक परिवर्तन का संकेत भी है। लोकतांत्रिक शासन अब केवल सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया नहीं रह गया है; यह निरंतर संवाद, पारदर्शिता, डेटा–आधारित नीति–निर्माण, तकनीकी नवाचार और नागरिक उत्तरदायित्व की प्रणाली बनता जा रहा है।

युवाओं की अपेक्षाएँ जितनी बढ़ी हैं, उतनी ही शासन की जवाबदेही भी बढ़ी है। इसलिए लोकतांत्रिक संस्थाओं को अधिक लचीला, समावेशी, तकनीक–सक्षम और नागरिक–केंद्रित बनाना समय की आवश्यकता है।

युवा–केंद्रित सार्वजनिक नीतियाँ

इक्कीसवीं सदी में लोकतांत्रिक शासन की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी सार्वजनिक नीतियाँ युवाओं की बदलती आकांक्षाओं को किस सीमा तक संबोधित करती हैं। पारंपरिक कल्याणकारी नीतियों के स्थान पर आज ऐसी नीतियों की आवश्यकता है जो युवाओं को केवल लाभार्थी (Beneficiaries) नहीं, बल्कि विकास प्रक्रिया के सक्रिय भागीदार (Partners in Development) के रूप में स्वीकार करें। युवा–केंद्रित सार्वजनिक नीतियाँ शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, डिजिटल सशक्तिकरण, नवाचार, पर्यावरणीय उत्तरदायित्व तथा लोकतांत्रिक सहभागिता जैसे विविध आयामों को समाहित करती हैं।

लोकतांत्रिक शासन में सार्वजनिक नीति केवल समस्याओं का समाधान करने का माध्यम नहीं होती, बल्कि नागरिकों और राज्य के बीच विश्वास निर्माण का आधार भी होती है। जब युवा अनुभव करते हैं कि उनकी आकांक्षाएँ नीति–निर्माण का हिस्सा हैं, तब उनकी लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता और नागरिक उत्तरदायित्व दोनों सुदृढ़ होते हैं।

1. शिक्षा एवं कौशल विकास आधारित नीतियाँ

ज्ञान–आधारित अर्थव्यवस्था में शिक्षा और कौशल विकास लोकतांत्रिक सशक्तिकरण के प्रमुख साधन हैं। युवाओं की अपेक्षा है कि शिक्षा प्रणाली उन्हें केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने तक सीमित न रखे, बल्कि उन्हें नवाचार, आलोचनात्मक चिंतन, नेतृत्व, डिजिटल दक्षता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करे।

युवा–केंद्रित शिक्षा नीति में निम्नलिखित विशेषताएँ अपेक्षित हैं—

- बहुविषयक (Multidisciplinary) शिक्षा।
- अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहन।
- डिजिटल अधिगम संसाधनों का विस्तार।
- उद्योग एवं विश्वविद्यालय के बीच सहयोग।
- उद्यमिता एवं स्टार्टअप शिक्षा।
- जीवन–कौशल तथा नागरिक शिक्षा का समावेश।

ऐसी शिक्षा प्रणाली युवाओं को लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ–साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में भी सशक्त बनाती है।

2. रोजगार एवं उद्यमिता उन्मुख नीतियाँ

युवा अपेक्षाओं का सबसे महत्वपूर्ण आधार सम्मानजनक रोजगार है। लोकतांत्रिक शासन को ऐसी आर्थिक नीतियाँ विकसित करनी चाहिए जो युवाओं की प्रतिभा और नवाचार क्षमता का अधिकतम उपयोग कर सकें।

रोजगार संबंधी नीतियों में निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए—

- भविष्य के उद्योगों के अनुरूप कौशल विकास।
- स्टार्टअप एवं सामाजिक उद्यमिता को प्रोत्साहन।
- ग्रामीण युवाओं के लिए स्थानीय रोजगार अवसर।
- हरित अर्थव्यवस्था (Green Economy) में रोजगार।
- महिलाओं एवं दिव्यांग युवाओं के लिए समावेशी रोजगार कार्यक्रम।
- अनुसंधान आधारित रोजगार सृजन।

ऐसी नीतियाँ आर्थिक विकास के साथ सामाजिक स्थिरता को भी सुदृढ़ करती हैं।

3. डिजिटल नागरिकता और सुशासन

डिजिटल तकनीक ने लोकतांत्रिक शासन को अधिक पारदर्शी, सुलभ और उत्तरदायी बनाया है। आज का युवा प्रशासनिक सेवाओं, शिकायत निवारण, सार्वजनिक सूचना तथा नीति–निर्माण में डिजिटल माध्यमों के उपयोग की अपेक्षा करता है।

युवा–केंद्रित डिजिटल शासन के प्रमुख आयाम हैं—

- ई–गवर्नेंस सेवाओं का विस्तार।
- डिजिटल पहचान और सुरक्षित ऑनलाइन सेवाएँ।
- ओपन गवर्नमेंट डेटा।
- डिजिटल परामर्श मंच।
- ऑनलाइन नागरिक सहभागिता।
- साइबर सुरक्षा और डिजिटल गोपनीयता।

हालाँकि, डिजिटल शासन की सफलता के लिए डिजिटल साक्षरता और डिजिटल समानता सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक है।

4. लोकतांत्रिक नेतृत्व विकास

लोकतंत्र की स्थिरता के लिए केवल अनुभवी नेतृत्व ही पर्याप्त नहीं है; नई पीढ़ी के नेतृत्व का विकास भी आवश्यक है। युवाओं को राजनीतिक प्रक्रियाओं से जोड़ने के लिए विभिन्न संस्थागत उपाय किए जा सकते हैं—

- युवा संसद।
- स्थानीय निकायों में युवा प्रतिनिधित्व।
- विश्वविद्यालय स्तरीय लोकतांत्रिक मंच।
- सार्वजनिक नीति इंटर्नशिप।
- नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- नागरिक सहभागिता अभियान।

इन पहलों से लोकतांत्रिक संस्कृति अधिक जीवंत और सहभागी बनती है।

लोकतांत्रिक शासन के लिए नीतिगत सुझाव

युवाओं की बदलती अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित नीतिगत सुझाव प्रस्तुत किए जा सकते हैं—

1. युवा–केंद्रित नीति–निर्माण

राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर नीति निर्माण की प्रत्येक प्रक्रिया में युवाओं के प्रतिनिधित्व को संस्थागत रूप दिया जाना चाहिए। युवा सलाहकार परिषदों (Youth Advisory Councils) की स्थापना इस दिशा में प्रभावी कदम हो सकती है।

2. गुणवत्तापूर्ण एवं समावेशी शिक्षा

शिक्षा को केवल डिग्री प्राप्ति का माध्यम न मानकर रोजगार, नवाचार और लोकतांत्रिक नागरिकता से जोड़ा जाना चाहिए।

डिजिटल शिक्षा, अनुसंधान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कौशल विकास को पाठ्यक्रम का अभिन्न भाग बनाया जाना चाहिए।

3. रोजगार और उद्यमिता को प्राथमिकता
सरकार को उद्योगों, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के बीच समन्वय स्थापित कर रोजगारोन्मुख शिक्षा और नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना चाहिए।

4. डिजिटल लोकतंत्र का विस्तार
सार्वजनिक नीति निर्माण में डिजिटल परामर्श, ऑनलाइन सुझाव, ई–जनसुनवाई तथा नागरिक प्रतिक्रिया तंत्र को अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए।

5. मीडिया एवं डिजिटल साक्षरता
फेक न्यूज़, दुष्प्रचार और डिजिटल ध्रुवीकरण की चुनौतियों से निपटने के लिए विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में मीडिया साक्षरता तथा डिजिटल नागरिकता संबंधी कार्यक्रम प्रारम्भ किए जाने चाहिए।

6. पारदर्शिता और जवाबदेही
सभी सार्वजनिक संस्थाओं में पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया, सामाजिक लेखा परीक्षण (Social Audit), ओपन डेटा तथा समयबद्ध सेवा वितरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

7. मानसिक स्वास्थ्य को नीति का भाग बनाना
युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य, परामर्श सेवाओं, तनाव प्रबंधन और मनोसामाजिक सहायता को सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति में प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिए।

8. पर्यावरणीय नेतृत्व
युवाओं को जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी के अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

9. लोकतांत्रिक मूल्यों का संवर्धन
विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में संविधान, नागरिक अधिकार, कर्तव्य, सहिष्णुता, बहुलवाद तथा लोकतांत्रिक संस्कृति पर आधारित नागरिक शिक्षा को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

10. अनुसंधान आधारित नीति–निर्माण
युवा अपेक्षाओं का नियमित सर्वेक्षण कर सार्वजनिक नीतियों का मूल्यांकन साक्ष्य–आधारित (Evidence–Based) ढंग से किया जाना चाहिए। इससे नीतियाँ अधिक प्रभावी और उत्तरदायी बन सकेंगी।

निष्कर्ष
इक्कीसवीं सदी का युवा लोकतंत्र को केवल शासन प्रणाली के रूप में नहीं, बल्कि सहभागिता, पारदर्शिता, समान अवसर, सामाजिक न्याय और उत्तरदायित्व पर आधारित एक जीवंत सामाजिक अनुबंध के रूप में देखता है। उसकी अपेक्षाएँ पारंपरिक राजनीतिक विमर्श से आगे बढ़कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सम्मानजनक रोजगार, डिजिटल सुशासन, पर्यावरणीय उत्तरदायित्व, लैंगिक समानता, नवाचार, सामाजिक समावेशन और नैतिक नेतृत्व तक विस्तृत हो चुकी हैं। यह परिवर्तन लोकतांत्रिक शासन के लिए चुनौती भी है और अवसर भी।

राजनीतिक नेतृत्व को यह समझना होगा कि आज का युवा केवल चुनावों के समय सक्रिय मतदाता नहीं है, बल्कि वह नीति–निर्माण, सामाजिक परिवर्तन और लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व का सक्रिय सहभागी बनना चाहता है। इसलिए लोकतांत्रिक संस्थाओं को अधिक पारदर्शी, समावेशी, तकनीक–सक्षम और संवादपरक बनाना समय की आवश्यकता है। इसके साथ ही शिक्षा, रोजगार, डिजिटल सशक्तिकरण और नागरिक सहभागिता पर आधारित सार्वजनिक नीतियाँ लोकतंत्र की गुणवत्ता को नई ऊँचाइयों तक पहुँचा सकती हैं।

यह अध्ययन इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि लोकतांत्रिक शासन की दीर्घकालिक सफलता केवल संवैधानिक संस्थाओं की मजबूती पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि शासन युवाओं की आकांक्षाओं को कितनी संवेदनशीलता, दूरदर्शिता और उत्तरदायित्व के साथ स्वीकार करता है। यदि युवाओं को नीति–निर्माण, नेतृत्व विकास और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में वास्तविक भागीदारी प्रदान की जाती है, तो लोकतंत्र अधिक विश्वसनीय, नवाचारी, समावेशी और सतत बन सकता है। इस प्रकार युवा केवल भविष्य के नागरिक नहीं, बल्कि वर्तमान लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण साझेदार और परिवर्तन के प्रेरक हैं।

संदर्भ

1. Almond GA, Verba S. The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Princeton University Press, 1963.
2. Dalton RJ. The Good Citizen: How a Younger Generation Is Reshaping American Politics. CQ Press, 2008.
3. Government of India. National Education Policy 2020. Ministry of Education, 2020.
4. Inglehart R. Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic and Political Change in 43 Societies. Princeton University Press, 1997.
5. Norris P. Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited. Cambridge University Press, 2011.
6. OECD. Governance for Youth, Trust and Intergenerational Justice. OECD Publishing, 2021.
7. Putnam RD. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. Simon & Schuster, 2000.
8. United Nations. Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. United Nations, 2015.
9. United Nations Development Programme. Human Development Report 2021/2022. UNDP, 2022.
10. UNESCO. Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education. UNESCO, 2021.
11. World Bank. World Development Report 2023: Migrants, Refugees and Societies. World Bank, 2023.
12. World Economic Forum. Global Risks Report 2024. World Economic Forum, 2024.
13. World Economic Forum. Future of Jobs Report 2024. World Economic Forum, 2024.